www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 मोदी के बहाने और भागवत कथा के मायने

3 पी.डब्ल्यू.डी. यूनियन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी...

4 ज्ञान, न्याय, सेवा, व्यापार और उद्योग एक साथ...

वर्ष: 9 | अंक: 233 | दिल्ली, मंगलवार, 17 जून 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

मुंबई के दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट पर पुलिस

मुंबई (एजेन्सी)। मुंबई के कई इलाकों में तनाव फैल गया, जब दो प्रमुख स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार, देवनार में कनकिया इंटरनेशनल स्कूल और समता नगर में रयान इंटरनेशनल स्कूल को परेशान करने वाले संदेशों में निशाना बनाया गया, जिसमें न केवल संस्थानों को धमकी दी गई, बल्कि मुंबई के विभिन्न हिस्सों में बम विस्फोटों की भी चेतावनी दी गई। अलर्ट के बाद, देवनार और समता नगर से पुलिस दल तुरंत संबंधित परिसरों में पहुंचे, गहन तलाशी ली और सुरक्षा प्रोटोकॉल को कड़ा किया। हालांकि, अब तक जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। संबंधित धाराओं के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और ईमेल की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए साइबर सेल को शामिल किया गया है। यह ताजा धमकी मुंबई के बीकेसी इलाके में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को मिली इसी तरह की धमकी के कुछ ही दिनों बाद आई है।

जनगणना की अधिसूचना जारी, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर समेत दो राज्यों में 2026 में होगी शुरू

नई दिल्ली (एजेन्सी)। सरकार ने सोमवार दोपहर कहा कि भारत की जनसंख्या की रिकॉर्डिंग, जिसमें जाति जैसे महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं, 1 अक्टूबर, 2026 की मध्यरात्रि से लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुरू होगी। देश के बाकी हिस्सों के लिए गिनती 1 मार्च, 2027 की मध्यरात्रि से शुरू होगी। इससे पहले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह सचिव, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनगणना की तैयारी की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक राज्य में जनगणना दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में, यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन या एचएलओ में, प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना या पीई में प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी एकत्र की जाएगी।

साइप्रस भारत के लिए खासकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार हैः प्रधानमंत्री मोदी

संजना भारती/पीआईबी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति महामहिम निकोस क्रिस्टोडौलिडेस के साथ लिमासोल में साइप्रस और भारत के व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ गोलमेज वार्ता की। प्रतिभागियों में बैंकिंग, वित्तीय संस्थानों, विनिर्माण, रक्षा, रसद, समुद्री, शिपिंग, प्रौद्योगिकी, नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, एआई, आईटी सेवाओं, पर्यटन और गतिशीलता जैसे विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे।

पिछले 11 वर्षों में भारत के तेजी से आर्थिक परिवर्तन की जानकारी देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगली पीढ़ी के सुधारों, नीतिगत पूवार्नुमान, स्थिर राजनीति और व्यापार करने में आसानी से प्रेरित होकर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। नवाचार, डिजिटल क्रांति, स्टार्ट-अप और भविष्य के बुनियादी ढांचे के विकास को दी जा रही प्राथमिकता पर बल देते हुए, श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि भारत में नागरिक उड्डयन, बंदरगाह, जहाज निर्माण, डिजिटल भुगतान और हरित विकास क्षेत्रों में स्थिर वृद्धि ने साइप्रस की कंपनियों के लिए भारत के साथ साझेदारी

करने के असंख्य अवसर खोले हैं। उन्होंने भारत की कुशल प्रतिभा और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र की ताकत की जानकारी दी और भारत की विकास गाथा में योगदान देने वाले नए और उभरते क्षेत्रों के रूप में विनिर्माण, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों की जानकारी दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि साइप्रस भारत के लिए खासकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में नए निवेश के लिए साइप्रस की गहरी रुचि का स्वागत किया। वित्तीय सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक जुड़ाव की संभावना पर बल देते हुए, दोनों नेताओं ने एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी, गुजरात और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया।

एनआईपीएल (एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड) और यूरोबैंक साइप्रस ने दोनों देशों के बीच सीमा पार भुगतान के लिए यूपीआई शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। इससे पर्यटकों और व्यवसायों को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री ने भारत-ग्रीस-साइप्रस (आईजीसी) व्यापार और निवेश परिषद के शुभारंभ का भी स्वागत किया, जो शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने इस तथ्य का स्वागत किया कि कई भारतीय कंपनियां साइप्रस को यूरोप के प्रवेश द्वार और आईटी सेवाओं, वित्तीय प्रबंधन और पर्यटन के केंद्र के रूप में देखती हैं।

साइप्रस अगले वर्ष यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने वर्ष के अंत तक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने के बारे में आशा व्यक्त की, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि व्यापार गोलमेज चर्चा ने व्यावहारिक सुझाव दिए हैं जो संरचित आर्थिक रोडमैप का आधार बनेंगे। इससे व्यापार, नवाचार और रणनीतिक क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग सुनिश्चित होगा।

साझा आकांक्षाओं और भविष्य-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, भारत और साइप्रस गतिशील और पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक सहयोग के नए युग के लिए तैयार हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने अत्याधुनिक एमआरएस मशीनों और एंटी-स्मॉग गन मशीनों का किया निरीक्षण

'वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हर विधानसभा को मिलेगी हाई-टेक मशीन'

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय के बाहर वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक मशीनों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। उन्होंने आधुनिक तकनीक से लैस इन मशीनों की कार्यकुशलता का संचालन ध्यानपूर्वक देखा और अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली को स्वच्छ व प्रदूषण रहित बनाने के लिए अत्याधुनिक (हाईटेक) मशीनों की खरीद और तैनाती की जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक मशीन की तैनाती हो। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित पर्यावरण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। सड़कों के किनारे जमी गंदगी, धूल और मिट्टी राजधानी की हवा को लगातार प्रदूषित कर नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी। इस चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने इस वर्ष के बजट में विशेष प्रावधान किया है, जिसके तहत सड़कों की सफाई के लिए अत्याधुनिक मशीनों की तैनाती की जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि पूरे वर्ष दिल्ली की सड़कों पर नियमित सफाई और वॉटर स्प्रिंकलिंग सुनिश्चित किया जाए।

इसी दिशा में विभिन्न अत्याधुनिक मशीनों का प्रदर्शन (डेमो) किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक मशीन की तैनाती हो।

सीएम नायब सैनी ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की निविदा राशि वाली प्रमुख सिंचाई और जल संसाधन परियोजनाओं की समीक्षा की

'इन परियोजनाओं का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ाना, सिंचाई दक्षता में सुधार करना'

संजना भारती संवाददाता

चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार सिंचाई एवं जल ढांचे को मजबूत करने के लिए दृढ़ एव ठोस कदम उठा रही है, जिसके तहत सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पांच प्रमुख परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, जिनमें से प्रत्येक में 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ाना, सिंचाई दक्षता में सुधार करना शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज यहां सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि परियोजनाओं की इंजीनियरिंग ड्राइंग में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। ड्राइंग के अनुमोदन में देरी के चलते परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होता है। उन्होंने ड्राइंग में अनुमोदन में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने

परियोजनाओं में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि दादूपुर से हमीदा हेड तक नई समानांतर लाइन चैनल (पीएलसी) और डब्ल्यूजेसी का आधुनिकीकरण 274.87 करोड़ रुपये के साथ किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य गैर-मानसून अवधि के दौरान हथिनीकुंड बैराज से होने वाले रिसाव के नुकसान को कम करना है। अब तक 64.5 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। परियोजना को मार्च, 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डब्ल्यूजेसी ब्रांच (75.25 किमी) तक ऑग्मेंटेशन नहर का पुनर्निर्माण 383 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इस परियोजना का 81 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और जून, 2025 तक पूरा होने की संभावना है। इसी प्रकार पीडी ब्रांच (मुनक से खुबडु हेड) की लाइनिंग और रीमॉडलिंग का कार्य 197.80 करोड़ रुपए से किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत 145.25 किलोमीटर में कंक्रीट लाइनिंग का कार्य शामिल है। उन्होंने कहा कि 145.99 करोड़ रुपये की लागत वाली हथिनीकुंड बैराज के डाउनस्ट्रीम में डायाफ्राम वॉल के निर्माण की संरचनात्मक सुरक्षा परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना (एनपीसीआईएल) के तहत गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पानी की आपूर्ति के लिए 442.64 करोड़ रुपये की लागत से आरसीसी बैरल और लिंक चैनल का निर्माण किया जा रहा है। इसका अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि मानसून 2025 के लिए सिंचाई विभाग ने मानसून के दौरान निर्बाध जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की है। इसमें हथिनीकुंड बैराज पर अस्थायी सुरक्षात्मक कार्य और महत्वपूर्ण नहरों में निर्वहन क्षमता को अधिकतम करना शामिल है। हरियाणा सरकार इन मेगा-प्रोजेक्ट्स के समय पर क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है, जो राज्य की जल सुरक्षा और कृषि स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। चुनौतियों पर काबू पाने और तेजी से काम पूरा करने के लिए निरंतर निगरानी, अंतर-विभागीय समन्वय और हितधारक जुड़ाव को प्राथमिकता दी जा रही है।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन, ईआईसी सतबीर कादियान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से कोरिया एनवायरनमेंटल इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

'दिल्ली के ग्रीन एक्शन प्लान को मिलेगा वैश्विक तकनीक व सहयोग'

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में कोरिया एनवायरनमेंटल इंडस्ट्री एसोसिएशन के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल में पार्क जियोंग वूक (उप निदेशक, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ब्यूरो-ग्लोबल ग्रीन प्रोजेक्ट टीम), चोई जीना (सेक्रेटरी जनरल, KEIA) और इम सु ह्यून (प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन टीम, KEIA) शामिल रहीं।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कोरिया के ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस कार्यक्रम के तहत दिल्ली के ग्रीन एक्शन प्लान को समर्थन देने हेतु संभावित परियोजनाओं पर चर्चा करना था।

इस मीटिंग की शुरूआत 12 जून को हुई दुखद AI-171 विमान दुर्घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मिनट के मौन के साथ की गई। इस बैठक के बाद माननीय मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि "दिल्ली सरकार औद्योगिक उत्सर्जन घटाने, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने व जलवायु के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रही है। KEIA के साथ संवाद हमें कोरिया की उन्नत ग्रीन टेक्नोलॉजी दिल्ली लाने का अवसर देगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन व माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हम दिल्ली को वैश्विक दक्षिण का सस्टेनेबल अर्बन डेवेलपमेंट मॉडल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

KEIA ने हाइड्रोजन एनर्जी, अपसाइकलिंग, पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रेजेंटेशन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली सरकार के विभागों के साथ पायलट प्रोजेक्ट्स व तकनीकी सहयोग हेतु तत्परता व्यक्त की।

इस दौरान माननीय मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "KEIA की रिसर्च पार्टनरशिप व नॉलेज शेयरिंग में रुचि सराहनीय है। उनका गवर्नमेंट-इंडस्ट्री-अकैडेमिया मॉडल दिल्ली के एकीकृत ग्रीन गवर्नेंस दृष्टिकोण से मेल खाता है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार के हमारे प्रयास और भी प्रभावी बन सकते हैं।"

दोनों पक्षों ने भविष्य में दिल्ली में कोरिया-भारत एनवायरनमेंटल इनोवेशन फोरम आयोजित करने की संभावना पर भी चर्चा की, जो कोरियाई टेक्नोलॉजी प्रदाताओं, भारतीय शहरी निकायों व वैश्विक विशेषज्ञों को एक साझा मंच पर लाकर पर्यावरणीय समाधान विकसित करने में मदद करेगा।

KEIA टीम ने दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति, ई-वेस्ट प्रबंधन, निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन व मिस्ट स्प्रिंकलर की अनिवार्यता व प्रदूषण नियंत्रण के कड़े अनुपालन जैसे कदमों की सराहना की। साथ ही दिल्ली के ग्रीन एक्शन प्लान में दीर्घकालिक भागीदारी का आश्वासन भी दिया।

यह बैठक दिल्ली की उन अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राजधानी की वायु गुणवत्ता सुधारने, औद्योगिक प्रदूषण घटाने व जलवायु अनुकूलता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

चौधरी ब्रह्म प्रकाश का दूरदर्शी नेतृत्व और अमिट विरासत आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगीः विजेंद्र गुप्ता

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी का दूरदर्शी नेतृत्व और उनकी अमर विरासत सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। उन्होंने यह वक्तव्य दिल्ली विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान, दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री स्व. चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की 107वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दिया।

इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में अध्यक्ष गुप्ता के अलावा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट; लोक निर्माण एवं विधायी कार्य मंत्री परवेश साहिब सिंह; समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, सहकारिता एवं निर्वाचन मंत्री इन्द्राज सिंह; नगर निगम के उपमहापौर श्री जय भगवान यादव तथा मुख्य सचेतक श्री अभय वर्मा भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के जीवन से जुड़ी दुर्लभ और ऐतिहासिक झलकियों की एक विशेष फोटो प्रदर्शनी भी विधानसभा परिसर में लगाई गई। अपने संबोधन में माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि 15 मार्च 1979 को तत्कालीन नेता स्व. श्री साहिब सिंह वर्मा द्वारा दिल्ली विधानसभा परिसर में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की प्रतिमा की स्थापना की गई थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि स्व. साहिब सिंह वर्मा स्वयं चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी से गहराई से प्रभावित थे और उन्हें अपना राजनीतिक मार्गदर्शक मानते थे।

श्री गुप्ता ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि विगत वर्षों में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी जैसे महान नेता को वैसा सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे। उन्होंने बताया कि मात्र 32 वर्ष की आयु में वे वर्ष 1952 में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने और बाद में चार बार संसद सदस्य के रूप में चुने गए-जो उनकी जनप्रियता को दर्शाता है। उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी

को एक आदर्श जननेता बताया और कहा कि ऐसे महापुरुष सदैव जीवित रहते हैं। हमें उनकी विरासत को संरक्षित रखना चाहिए। लोक निर्माण एवं विधायी कार्य मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने संसद में सदर और बाहरी दिल्ली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और बाद में चौधरी चरण सिंह के साथ भी कार्य किया। उन्होंने यह भी स्मरण किया कि उनके पिता स्व. साहिब सिंह वर्मा ने वर्ष 1979 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी का चित्र विधानसभा में स्थापित किया था। समाज कल्याण मंत्री श्री इन्द्राज सिंह ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के आजीवन समर्पण को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा वंचितों और कमजोर वर्गों के हित में कार्य किया और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी-जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

मुख्य सचेतक श्री अभय वर्मा ने कहा कि जिन विभूतियों ने दिल्ली की लोकतांत्रिक पहचान को गढ़ा है, उन्हें याद रखना और उनकी स्मृति को जीवंत रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

जल्द आगे बढ़ेगा मॉनसून, मिल रही अच्छी परिस्थितियां

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और इलाकों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की जानकारी दी है। मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि अब मॉनसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। मानसून 16 जून तक सक्रिय अवस्था में रह सकता है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और कोंकण एवं गोवा में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और अत्यंत भारी वर्षा (20 सेमी से अधिक) होने की संभावना है। यह मध्य अरब सागर, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तरी अरब सागर और गुजरात के शेष भागों की ओर बढ़ गया। मानसून की उत्तरी सीमा वेरावल, भावनगर, वडोदरा, खरगोन, अमरावती, दुर्ग, बरगढ़, चांदबली, संधेल द्वीप और बालुरघाट से होकर गुजरी है। पिछले सप्ताह एक पखवाड़े के अंतराल के बाद मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई है।

सम्पादकीय

एक दूसरे के खून के प्यासे बने ईरान और इजराइल

ईरान और इजराइल एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। दोनों के बीच इस समय जो वार-पलटवार चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि दुनिया में एक-दूसरे के यही सबसे बड़े दुश्मन देश हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दशकों से एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए ईरान और इजराइल कभी गहरे मित्र भी थे? वैसे ईरान और इजराइल की मित्रता की बात भले कोरी कल्पना लगे लेकिन इतिहास इस दोस्ती का गवाह है। हम आपको बता दें कि 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई थी तब बहुत से मुस्लिम बहुल देशों ने उसे मान्यता देने से इंकार कर दिया था। लेकिन उस दौर में ईरान एक अपवाद था। यह बात आज के ईरान-इजराइल संबंधों को देखते हुए चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन 1948 से 1970 के बीच ईरान और इजराइल के बीच गहरे परन्तु छुपे हुए मैत्री संबंध थे, जो कूटनीति, सैन्य सहयोग और व्यापार पर आधारित थे। वैसे ईरान ने इजराइल को उसकी स्थापना के बाद सार्वजनिक रूप से तत्काल मान्यता नहीं दी थी, लेकिन 1950 में इजराइल को "डि-फैक्टो" मान्यता दे दी गई थी। इसका मतलब था कि दोनों देशों ने औपचारिक रूप से दूतावास नहीं खोले, लेकिन व्यावसायिक और कूटनीतिक संबंध धीरे-धीरे स्थापित होते रहे। इस मैत्री के पीछे कारण था साम्य हित। दरअसल दोनों की स्थिति उस समय अरब राष्ट्रों से घिरे हुए देशों की थी। यह दोनों अरब देशों के दुश्मन थे इसीलिए इनके बीच एक रणनीतिक साझेदारी की जरूरत महसूस हुई। हम आपको यह भी बता दें कि इजराइल और उस समय के ईरान के शाह (मोहम्मद रजा पहलवी), दोनों ही अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों के करीबी माने जाते थे। यह एक और कारण था जो दोनों देशों को एक-दूसरे के करीब लाया। इसके अलावा, इजराइल को तेल की जरूरत थी, जोकि ईरान के पास भरपूर मात्रा में था। इस साझेदारी के जरिए इजराइल को गुप्त रूप से तेल की आपूर्ति होती रही। इसके बदले में इजराइल ने ईरान को कृषि, जल प्रबंधन और तकनीकी मदद दी। 1950-70 के दशक में ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार के दौरान इजराइल ने तेल के बदले ईरान को हथियार भी दिए थे। इसके अलावा, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की सवाक के बीच भी घनिष्ठ सहयोग था। मोसाद ने सवाक को खुफिया ट्रेनिंग दी और तकनीकी उपकरण भी उपलब्ध कराए। यह सहयोग विशेष रूप से 1960 के दशक में मजबूत हुआ। साथ ही "Trident" परियोजना एक गुप्त योजना थी जिसमें इजराइल और ईरान ने मिलकर मिसाइल टेक्नोलॉजी और सैन्य शोध पर काम किया। साथ ही इजराइली विशेषज्ञों ने ईरान में कृषि सुधार, सिंचाई प्रणाली और जल प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं में भी अहम भूमिका निभाई। हम आपको बता दें कि 1970 के दशक में यह संबंध अपने चरम पर था, लेकिन ईरान में इस्लामी आंदोलन के जोर पकड़ने के साथ इसमें दरार आने लगी। शाह के शासन के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था और 1979 की इस्लामी क्रांति इस मैत्री का अंत लेकर आई। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से हटाकर आयतुल्ला खामेनेई के नेतृत्व में ईरान में एक धार्मिक सरकार बनते ही इजराइल को दुश्मन घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही इजराइल के दूतावास को बंद करके उसे फिलिस्तीनी संगठन PLO को दे दिया गया। इजराइल को इस्लाम का भी दुश्मन घोषित करने के बाद ईरान ने हिजबुल्ला और हमास को मदद देनी शुरू की जोकि आज तक जारी है। वैसे इस तरह की भी रिपोर्टें समय-समय पर आती रहीं कि ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी के दौर में भी गुप्त रूप से कारोबार चलता रहा। बताया जाता है कि 1980 में जब ईरान और इराक के बीच जंग हुई, तो इजराइल को महसूस हुआ कि इराक ज्यादा खतरनाक है। इसलिए, अमेरिका और इजराइल ने गुपचुप तरीके से ईरान को लड़ने के लिए हथियार भेजे थे। लेकिन जब 1990 के दशक में ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो इजराइल ने ईरान को इसे सबक सिखाने की ठान ली और अब जब तेहरान परमाणु बमों के निर्माण से चंद कदम ही दूर रह गया था तो इजराइल ने बड़ा हमला करते हुए आयतुल्ला खामेनेई के सपनों को तोड़ डाला। इजराइल ने सीधा हमला करने से पहले ईरान के हमास और हिज्बुल्ला जैसे सहयोगियों की कमर तोड़ी और पिछले कुछ महीनों में कई अभियानों के माध्यम से अपनी मारक क्षमता को भी परखा, उसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की गयी। बहरहाल, देखा जाये तो 1948 से 1970 तक का ईरान-इजराइल संबंध एक ऐसा अध्याय है जो आज के उथल-पुथल भरे पश्चिम एशिया की राजनीति में लगभग भुला दिया गया है। इस काल में दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक और आर्थिक संबंध थे, जो आज की स्थिति को देखते हुए विरोधाभासी प्रतीत होते हैं।

जयंती

कैलाश नाथ काटजू

जन्म-17 जून, 1887, मालवा, मध्य प्रदेश; मृत्यु-17 फरवरी, 1968) मध्य प्रदेश राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। इन्होंने जनवरी, 1957 से मार्च, 1962 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया था। कैलाश नाथ काटजू बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना भी की थी। भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी इनका विशेष योगदान था।

पुण्यतिथि

जीजाबाई

जन्म: 12 जनवरी, 1598 ई., मृत्यु: 17 जून, 1674 ई.) शाहजी भोंसले की पत्नी तथा छत्रपति शिवाजी की माता थीं। इन्हें राजमाता जीजाबाई और साधारणत: जीजाई के नाम से जाना जाता था। अपने पति शाहजी भोंसले के द्वारा उपेक्षित कर दिये जाने पर भी वह अपने पुत्र शिवाजी की संरक्षिका बनी रहीं और उनके चरित्र, महत्त्वाकांक्षाओं तथा आदर्शों के निर्माण में सबसे अधिक योगदान दिया। शिवाजी के जीवन की दिशा निर्धारित करने में उनकी माता जीजाबाई का सबसे अधिक प्रभाव था।

कल मिलेंगे

पत्नी-मेरा वजन कैसे कम होगा?
पति-अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाती रहो.
महिला-अच्छा, पर ये किस समय करूं?
पति-जब कोई खाने को पूछे !

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।
RNI No. : DELHIN/2016/70240
Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

मोदी के बहाने और भागवत कथा के मायने

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने पहले मुस्लिम दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने के आदेश दिये, तो फिर महाकुम्भ में उनके प्रवेश पर रोक भी लगायी। हालांकि मोदी-योगी के नारे, उसी संगम में तब डूब गए, जब कुम्भ के हजारों भगदड़ प्रभावितों को प्रयागराज के मुसलमानों ने अपने घरों में शरण देकर गंगा-जमुनी तहजीब का उदाहरण पेश किया

-ओंकारेश्वर पांडेय

एक तरफ जहां देश का गोदी मीडिया खासकर टेलीविजन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की बजाय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफों के पुल बांधने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के भीतर बैठे कई नेता संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर टकटकी लगाये बैठे हैं, कि वे कब बोलेंगे। वे कम बोलते हैं। पर उनके बोलने से भाजपा हिल जाती है। और जब नहीं बोलते तो उनकी खामोशी बोलती है। हाल ही में संघ प्रमुख ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के संदर्भ में जो प्रतिक्रिया दी है, उससे मोदी खेमा निराश है।

नागपुर में कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय के समापन समारोह को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम हमले के बाद के घटनाक्रम पर सेना व सरकार की सराहना की। लेकिन अपनी ही पार्टी का नेता होने के बावजूद भागवत ने न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़िक्र किया, न ही 'ऑपरेशन सिंदूर' या 'सीजफायर' का, और 'हिंदू समाज' की जगह केवल 'समाज' शब्द का प्रयोग किया। यह चुप्पी और शब्दों का सावधानीपूर्वक चयन कई सवाल खड़े करता है। मोहन को मोदी का नाम लेने से परहेज क्यों। कारण आगे समझ में आयेंगे। लेकिन पहले बात अनुशासन की। संघ के पूर्व सरसंघचालक एम.एस. गोलवलकर (गुरुजी) कहते थे, "व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विचार महत्वपूर्ण है।" लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी संघ से बड़े ही नहीं बहुत बड़े होते गए। इसलिए भागवत की नाराजगी को समझना जरूरी है।

भागवत ने कहा कि, "पहलगाम की कायरतापूर्ण आतंकवादी घटना के पश्चात पाक प्रायोजित आतंकवादियों एवं उनके समर्थक पारितंत्र पर की जा रही निर्णायक कार्रवाई के लिए भारत सरकार के नेतृत्व और सैन्यबलों का हार्दिक अभिनंदन।" उन्होंने राजनीतिक दलों व समाज की भी प्रशंसा की, पर साथ ही कहा कि "इससे समस्या तो खत्म हुई नहीं।"

विपक्ष से लेकर रक्षा-राजनय और मीडिया विशेषज्ञ सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कई तो इसे मोदी सरकार का ब्लंडर भी कहने लगे हैं। दुनिया कुछ भी कहे, संघ प्रमुख का कहना मायने रखता है। और तब बहुत रखेगा, जब संघ समय पर निर्णय भी ले। मणिपुर की घटना के एक साल बाद संघ प्रमुख की प्रतिक्रिया आयी और अबतक हल नहीं निकला।

भागवत के इस बयान को केवल 'ऑफ-हैंड' टिप्पणी नहीं माना जा सकता। उनका यह कहना कि "संकट बरकरार है" और "समस्या का समाधान नहीं हुआ," 9 मई 2025 को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू होने के बाद भागवत ने देशवासियों से सेना और सरकार का समर्थन करने की अपील की थी, लेकिन अचानक हुए युद्धविराम ने संघ को असमंजस में डाल दिया। दशकों से भाजपा और संघ परिवार कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे हैं कि उसने 1971 सहित कई मौकों पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा नहीं किया। तो अब जबकि मोदी सरकार के समय सेना पाकिस्तान को घुटनों पर ला रही थी, तो युद्धविराम क्यों हुआ?

भागवत का बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष 'ऑपरेशन सिंदूर' पर संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा है। विपक्ष के प्रमुख सवाल हैं:

-विदेश मंत्री ने ऑपरेशन शुरू होने पर पाकिस्तान को क्यों सूचित किया?

-जब सेना जीत रही थी, तो युद्धविराम क्यों?

-सीजफायर की घोषणा अमेरिका ने क्यों की?

-ट्रंप ने 14 बार मध्यस्थता की बात कही, पर मोदी ने इसका खंडन क्यों नहीं किया?

-कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा रखने की बजाय अमेरिकी मध्यस्थता क्यों मानी गई?

-क्या ऑपरेशन में राफेल समेत पांच विमान गिरे, जैसा कि दावा किया गया?

भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक साक्षात्कार में कहा कि विमानों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वे क्यों गिरे। सरकार इन सवालों का जवाब देने से बच रही है। सवाल यह भी है कि जब पीएम मोदी ने 80 से अधिक देशों का दौरा किया, तो इस युद्ध में केवल दो-तीन देशों को छोड़कर कोई साथ क्यों नहीं आया? क्या यह विदेश नीति की नाकामी नहीं? इन मुद्दों पर भागवत का मौन बहुत कुछ कहता है।

भागवत ने इस बार अपने बयान में 'हिंदू समाज' के बजाय 'समाज' शब्द का इस्तेमाल किया। वे पहले भी कह चुके हैं कि "मुसलमान भी हिंदू हैं और समाज का हिस्सा हैं।"

पहलगाम हमले में आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर हत्या के नैरेटिव ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी। लेकिन कश्मीरी मुसलमानों ने आतंकवाद के खिलाफ रैलियां निकालकर इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने पहले मुस्लिम दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने के आदेश दिये, तो फिर महाकुम्भ में उनके प्रवेश पर रोक भी लगायी। हालांकि मोदी-योगी के नारे, उसी संगम में तब डूब गए, जब कुम्भ के हजारों भगदड़ प्रभावितों को प्रयागराज के मुसलमानों ने अपने घरों में शरण देकर गंगा-जमुनी तहजीब का उदाहरण पेश किया।

यूपी में मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। मस्जिदों पर तिरपाल, मंदिर खोजने, और औरंगजेब की कब्र खोदने जैसे मुद्दों पर संघ के भैयाजी जोशी को कहना पड़ा कि "औरंगजेब यहीं पैदा हुआ और उसकी कब्र यहीं रहेगी।"

संघ का मतभेद मोदी या भाजपा से नहीं मोदी की कार्यशैली से है। 2024 के चुनाव में भाजपा ने '400 पार' का नारा दिया और विपक्ष को दुश्मन की तरह देखते हुए आक्रामक प्रचार किया। मोदी ने 'मंगलसूत्र', 'घुसपैठिए' और 'बंटोगे तो कटोगे' जैसे सांप्रदायिक बयान दिए। भागवत समझाते रहे कि विपक्ष का भी सम्मान बराबर है। यह भी कहा कि "हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, बल्कि जीवन पद्धति है" और "मुसलमान और ईसाई भी समाज का हिस्सा हैं," लेकिन उनकी आवाजें मोदी के आक्रामक प्रचार के शोर में नक्कारखाने में तूती की तरह दब गयीं। राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर भी संघ प्रमुख ने राम की मयार्दा और उनके चरित्र को अपनाने की सीख दी थी। भागवत ने एक बार कहा था, "एक सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता।" संघ अपने शीर्ष नेता को मूल्यों, मयार्दा और अनुशासन की याद दिलाता रहा और मोदी सरकार अपने मन की बात करती रही। उल्टे मोदी ने 11 साल में पार्टी को स्व-केंद्रित बनाया, पार्टी की बजाय 'मोदी की गारंटी' को बढ़ावा दिया। और इसे चुनाव जीतने के लिए जरूरी बताकर संघ का मुंह बंद रखा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तभी से संघ भाजपा के संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। एक और बात संघ को चुभ गईझ पिछले लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि भाजपा अब बड़ी और सक्षम हो चुकी है, उसे संघ के निर्देश की आवश्यकता नहीं।

लोकसभा चुनाव में 240 सीटों के साथ अल्पमत में आये प्रधानमंत्री मोदी ने बिना भाजपा कार्यकारिणी की बैठक बुलाये या संघ से मशवरा किए बगैर एनडीए की बैठक बुलाकर खुद को फिर से नेता घोषित कर लिया। इसीलिए अब संघ अपने विश्वासपात्र को अध्यक्ष बनाना चाहता है, जबकि मोदी-शाह 2029 के लिए सरकार के साथ पार्टी पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं।

मोदी ने पहले तो 'बंटोगे तो कटोगे' जैसे सांप्रदायिक नारे दिए, लेकिन ईद पर 'सौगात ए मोदी' भेजकर भाजपा समर्थकों को असमंजस में डाल दिया। यही नहीं, जो संघ सावरकर के हिंदू एकता के बुनियादी विचारों पर खड़ा है और हमेशा जाति प्रथा के साथ आरक्षण का भी विरोधी रहा है, भागवत व स्वयं मोदी भी इसके खिलाफ बोल चुके हैं, उन्हीं मोदी ने अचानक अगली जनगणना में जातियों की गणना कराने की राहुल गांधी की मांग को मंजूरी दे दी, तो समूचा संघ परिवार हिल गया। यह सावरकर समेत समूचे संघ की सोच पर हमला था। भागवत भले ही यह कहते हों कि "मुसलमान भी हिंदू हैं और समाज का हिस्सा हैं", उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वे अब हिंदू एकता की बात नहीं करते। सवाल है कि जाति जनगणना के मोदी के फैसले के बाद संघ कार्यकर्ता अब शाखाओं में क्या कहेंगे।

संघ और मोदी-शाह के बीच एक अहम पेंच फंसा है - भाजपा के पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव का। यह मतभेद एक साल से जारी है। मार्च 2025 में मोदी नागपुर गए, और 30 मई को भागवत दिल्ली में मोदी से मिले, लेकिन मसला अनसुलझा रहा।

मोदी ने 75 साल की उम्र में नेताओं को रिटायर करने का नियम बनाया, आडवाणी, जोशी जैसे नेता रिटायर कर भी दिये गए। अब सितंबर 2025 में मोदी खुद 75 साल के होंगे। पार्टी नेता चाहते हैं कि यह नियम उन पर भी लागू हो। लेकिन वो पद छोड़ने के मूड में नहीं।

सूत्रों के मुताबिक मोदी खेमे ने भागवत को यह समझाने की कोशिश की है, कि उनकी सरकार संघ के सारे एजेंडे को पूरा कर चुकी है। बस एक पाक प्रायजित आतंकवाद का मसला बाकी है, इसलिए उन्हें सरकार के साथ पार्टी का भी पूरा नियंत्रण मिलना जरूरी है। लेकिन चूंकि पार्टी अध्यक्ष ही पार्टी के अगले प्रधानमंत्री का नाम तय करेगा, इसलिए मोदी अपनी पसंद का अध्यक्ष चुनना चाहते हैं, पर संघ अब मोदी को मौका देने के मूड में नहीं है।

इसीलिए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव अहम है। पार्टी अध्यक्ष तय होते ही यह भी तय हो जाएगा कि आखिरकार किसकी चली और आगे कौन बनेगा बादशाह।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार, रणनीतिकार, अनेक पुस्तकों के लेखक, रक्षा व विदेश मामलों के अध्येता और यूनेस्को से संबद्ध थिंक टैंक-गोल्डेन सिगनेचर्स के संस्थापक हैं।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

उद्देश्य से भटके संयुक्त राष्ट्र संघ को भंग क्यों नहीं करते?

रूस-यूक्रेन युद्ध में सीएसआईएस के जून 2025 के अनुमान के अनुसार रूस के लगभग 250,000 सैनिकों की मौत हुई। साढ़े सात लाख गंभीर रूप से घायल हैं। यूक्रेन की ओर से 21 मई 2025 तक 70,935 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। सीएसआईएस का जून 2025 अनुमान: कुल 400,000 हताहत (इसमें 60 हजार से एक लाख मारे और 300-340 हजार घायल हुए)। यूक्रेनी ऑफिशियल आंकड़े के अनुसार 43,000 मारे और 370,000 घायल हुए

-अशोक मधुप

संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य औचित्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, और विभिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में 51 देशों द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भावी युद्धों को रोका वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। आज 193 देश इसके सदस्य हैं। इतने बड़े संगठन का लगता है कि आज कोई देश कहना मानने को तैयार नहीं। सबकी अपनी ढपली अपना राग है। संयुक्त राष्ट्र संघ तमाशबीन बन कर रह गया है। लगभग एक साल आठ माह से इजरायल-हमास युद्ध चल रहा है। अब इजरायल से ईरान पर हमलाकर दिया है। इजरायल-ईरान युद्ध में बैलिस्टिक मिजाइल प्रयोग हो रही हैं। सवा दो साल से रूस-यूक्रेन युद्ध चल रहा है। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में की गई बरबादी पूरी दुनिया ने देखी। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव जीवन की बरबादी देख रहा है। यह असहाय बना बैठा है। मानव जीवन का विनाश रोकने के लिए वह कुछ नहीं कर पा रहा। उसकी भूमिका शून्य होकर रह गई है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर सकता। को देश उसकी मानने को तैयार नही।युद्ध रोकने की उसकी शक्ति नहीं तो उसका औचित्य क्या है? दुनिया के देश क्यों इस सफैद हाथी को पाले हैं। क्यों इसका खर्च वहन कर रह हैं। इस भंग क्यों नही कर दिया जाता। एक साल आठ माह से से हमास-इजरायल युद्ध चल रहा है। लगभग डेढ़ साल पूर्व हमास-इजरायल युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रयास हुए। कई बार प्रस्ताव के प्रयास हुए पर वीटो पावर वाले देशों के अडंगे के कारण कुछ नहीं हो सका। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस युद्ध को रोकने के लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव स्वीकार किया, किंतु इजरायल ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। होना यह चाहिए था कि प्रस्ताव होता कि हमास ने इस्राइल पर हमला किया है, वह इजरायल के नुकसान की भारपाई करे। इजरायल के बंदी रिहा करे। ये भी व्यवस्था होती कि भविष्य में हमास ऐसा दुस्साहस न कर सके। सब चाहते हैं कि इस्राइल युद्ध रोके। कोई ये पहल नही कर रहा कि पहले हमास इजरायल के बंदी रिहा करे। इजरायल के हमलों में बच्चों और महिलाओं के मरने की बात हो रही है। मुख्य मामला पीछे चला गया। अब ये सब बात बंद हो गई। साफ हो गया कि इजरायल मानने वाला नही है। हमास के हमले में इजरायल में बच्चों-महिलाओं का जिस तरह कत्ल किया गया, उनकी गर्दन काटी गई। उसका कहीं जिक्र नहीं हो रहा। इस तरह का दोहरा आचरण दुनिया का विखंडित ही करेगा, रोकेगा नही। पिछले तीन साल चार माह से रूस-यूक्रेन युद्ध जारी है। इस युद्ध में मरने और घायल होने वाले दोनों देशों के सैनिकों की संख्या पांच लाख के आसपास है। अपने सैनिकों की मौत के बारे में न रूस कुछ बता रहा है, न ही यूक्रेन।

रूस-यूक्रेन युद्ध में सीएसआईएस के जून 2025 के अनुमान के अनुसार रूस के लगभग 250,000 सैनिकों की मौत हुई। साढ़े सात लाख गंभीर रूप से घायल हैं। यूक्रेन की ओर से 21 मई 2025 तक 70,935 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। सीएसआईएस का जून 2025 अनुमानः कुल 400,000 हताहत (इसमें 60 हजार से एक लाख मारे और 300-340 हजार घायल हुए)। यूक्रेनी ऑफिशियल आंकड़े के अनुसार 43,000 मारे और 370,000 घायल हुए। यूएनएचसीआर के अनुसार, लगभग 10.6 मिलियन यूक्रेनियन विस्थापित हुए हैं। 3.7 मिलियन देश के अंदर, 6.9 मिलियन विदेश में विस्थापित हुए। यूएन के अनुसार यूक्रेन में लगभग 13,134 नागरिकों की मौत हुई है (2025 तक सत्यापित); 2022-2024 में मान्यता प्राप्त कुल नागरिक मृत्यु 50,000 तक हो सकती है। उधर इजराइल-हमास संघर्ष में इजरायल के 831 सैनिक मरे, 5,617 घायल हुए। 924 नागरिक मरे, 14,000 से ज्यादा घायल हुए। हमास/गाजा के 20,000 से ज्यादा मिलिटेंट मरे। (सटीक घायलों का डेटा नहीं) 55,000 से ज्यादा गाजाई महिला-बच्चे मरे। इतना सब होने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र इस युद्ध को नहीं रोक पाया। न रोक पा रहा है। इस युद्ध से दोनों देशों के विकास तो रुका ही। मानव कल्याण के लिए भवन, पुल, स्कूल और उद्योग खंडहर बन गए। इनके युद्ध के कारण दुनिया के अन्य देशों को होने वाली अनाज की आपूर्ति रुकी है। इससे पूरी दुनिया में मंहगाई बढ़ रही है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया। इससे रूस को भारी क्षति हुई। कई आधुनिक लड़ाकू विमान तबाह हुए। उसका जबाव रूस ने भी दिया। जिस तरह से रूस लड रहा है। मित्र देश यूक्रेन को पीदे से मदद कर रहे है, उससे लगता है कि गुस्साकर कभी भी रूस परमाणु हमला कर सकता है। किंतु इसकी किसी को चिंता नहीं। हमास-इजरायल युद्ध के बीच हुती विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइल से हमले किए। इजरायल समर्थक देशों के मालवाहक जहाजों पर मिसाइल दागीं। इस सब के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की नींद नही खुली।

आज संयुक्त राष्ट्र महासभा कुछ देश के हाथों की कठपुतली बन गया है। अन्य देश न अपनी ताकत का प्रयोग कर सकता है ना अपनी क्षमता का। संयुक्त राष्ट्र महासभा के गठन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विश्व में शांति कायम करना है। आज के हालात को देखते हुए लगता है कि अपने सबसे बड़े कार्य का दायित्व निभाने में वह सक्षम नहीं है। पांच वीटो पावर देश उसे अपनी मर्जी से नचा रहे हैं। उनके एकजुट हुए बिना संयुक्त राष्ट्र महासभा कुछ नहीं कर सकता। ये पांचों विटो पावर देश खुद खेमों में बंटे है। ऐसे में सर्व सम्मत प्रस्ताव पास होना एक प्रकार से नामुमकिन हो गया है। म्यांमार में पिछले दिनों सेना का जुल्म देखने को मिला। चीन में उइगर मुसलमानों पर जुल्म जग जाहिर हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पुलबामा कांड के बाद भारत ने पाकिस्तान में आंतकी ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए। पाकिस्तान के जवाब में चार दिन युद्ध चल कर रूका। संयुक्त राष्ट्र संघ इसे रोकने के लिए भी कुछ नहीं कर सका। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की बरबादी दुनिया ने देखी। पूरा विश्व सब देखता रहा। कोई कुछ नहीं कर सका। आज आतंकवाद पूरे विश्व की बड़ी समस्या है। सब जानते हैं कि कौन देश इसे पाल पोस रहे हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

भीषण जंग के बीच ईरान ने मानी भारत की बात, 10 हजार भारतीयों को निकालेगी सरकार

(एजेन्सी)।

इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच, तेहरान ने ईरानी शहरों में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत की अपील पर प्रतिक्रिया दी। वर्तमान में, लगभग 10,000 भारतीय ईरान में हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में छात्र हैं जो ईरान के विभिन्न चिकित्सा और धार्मिक संस्थानों में पढ़ रहे थे।

कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तेहरान ने कहा कि चल रहे संघर्ष के कारण ईरानी हवाई क्षेत्र बंद है, लेकिन अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सभी भूमि सीमाएँ वर्तमान में खुली हैं और इनका उपयोग भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए किया जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने भारत के राजनयिक मिशन को स्वीकृति प्रदान की है और चल रहे संघर्ष के बीच भारतीय राजनयिकों और नागरिकों दोनों की सुरक्षित निकासी को सुविधाजनक बनाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। बयान में कहा गया है कि मौजूदा स्थिति और देश के हवाई अड्डों के बंद होने के साथ-साथ कई राजनीतिक मिशनों द्वारा अपने राजनयिकों और नागरिकों को विदेश में स्थानांतरित करने के अनुरोध को देखते हुए, हम सूचित करते हैं कि सभी भूमि सीमाएँ पार करने के लिए खुली हैं।

भारत ने कहा कि ईरान में कुछ भारतीय छात्रों को देश के भीतर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अन्य संभव विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तेहरान में भारतीय दूतावास लगातार सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहा है और ईरान में भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनसे संपर्क कर रहा है। कुछ मामलों में, छात्रों को दूतावास की सुविधा के साथ ईरान के भीतर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। अन्य संभव विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक ताजा सार्वजनिक सलाह में सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से घर के अंदर रहने और आधिकारिक चैनलों की निगरानी करने को कहा। हम ईरान में सभी से अनुरोध करते हैं कि दूतावास से स्थिति पर अपडेट प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ें। कृपया ध्यान दें कि यह टेलीग्राम लिंक केवल उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो वर्तमान में ईरान में हैं।

सोने की कीमतें दो महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची

(एजेन्सी)।

सोना इन दिनों लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। सोने की कीमत में इन दिनों इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते दो महीने की उच्चतम कीमत सोने ने 16 जून को हासिल कर ली है। सोना लगातार चौथे कारोबारी सत्र में भी बढ़त हासिल किए रहा। इसके साथ ही सोने की कीमत दो महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।

वहीं सप्ताहांत में इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ गया है जिससे क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ी है। ऐसे में अब निवेशक सुरक्षित निवेश वाली परिसंपत्तियों की ओर आकर्षित हुए है। सत्र के आरंभ में 22 अप्रैल के बाद के उच्चतम स्तर को छूने के बाद, 0246 जीएमटी तक हाजिर सोना 0.3% बढ़कर 3,442.09 डॉलर प्रति औंस हो गया। अमेरिकी सोना वायदा 0.3% बढ़कर 3,461.90 डॉलर पर पहुंच गया। ओएएनडीए के एशिया प्रशांत क्षेत्र के वरिष्ठ बाजार विश्लेषक केल्विन वोंग ने कहा, "इस समय ईरान-इजराइल संघर्ष के कारण संयुक्त

राजनीतिक जोखिम प्रीमियम बढ़ रहा है, जिससे सोने की सुरक्षित मांग में वृद्धि हुई है।"

"अभी हम $3,400 से ऊपर स्पष्ट रूप से टूट चुके हैं और अल्पावधि में तेजी का रुझान बरकरार है। हम $3,500 पर प्रतिरोध स्तर देख रहे हैं और $3,500 के स्तर से ऊपर नई ऊंचाई को तोड़ने की संभावना है।" इजराइल और ईरान ने रविवार को ताजा हमले शुरू कर दिए, जिसमें नागरिक मारे गए और घायल हुए तथा व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की चिंताएं उत्पन्न हो गईं। दोनों सेनाओं ने विरोधी पक्ष के नागरिकों से आगे के हमलों के प्रति सावधानी बरतने का आग्रह किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इजरायल और ईरान एक समझौते पर मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी देशों को पहले लड़ना पड़ता है। भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के समय में सोने को अक्सर एक सुरक्षित परिसंपत्ति माना जाता है। इस सप्ताह निवेशकों की निगाहें केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के विभिन्न निर्णयों पर रहेंगी, जिनमें बुधवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर मुख्य नजर रहेगी। व्यापक रूप से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरें स्थिर रखेगा, तथा बाजार आगामी महीनों में संभावित ब्याज दरों में कटौती के संकेतों की प्रतीक्षा कर रहा है।

वायदा बाजार वर्ष के अंत तक दो बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जता रहे हैं, जिसकी शुरूआत संभवतः सितंबर में होगी, जिसे पिछले सप्ताह मुद्रास्फीति के आंकड़ों से बल मिला है। अन्यत्र, हाजिर चांदी 36.29 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही, प्लैटिनम 0.4% बढ़कर 1,233.87 डॉलर हो गया, जबकि पैलेडियम 1.3% बढ़कर 1,040.96 डॉलर हो गया।

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बुमराह-सिराज और जडेजा रच सकते हैं इतिहास

(एजेन्सी)।

20 जून से भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज होगा। जिसका पहला मुकाबला लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जाएगा। इस मैदान भारतीय टीम का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। भारत ने आखिरी बार यहां पिछला मुकाबला 2002 में जीता था। वहीं अगर इस मैदान पर भारत बनाम इंग्लैंड के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहां दोनों की अब तक कुल सात टेस्ट में भिड़ंत हुई है। जिसमें से इंग्लैंड ने चार मैच जीते हैं तो भारत को सिर्फ ही जीत नसीब हुई हैं जबकि एक टेस्ट ड्रॉ रहा है। इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम में युवा खिलाड़ी ज्यादा हैं। जिन्हें लीड्स में टेस्ट खेलने का अनुभव नहीं है, जिनमें खुद कप्तान शुभमन गिल भी शामिल हैं। सिर्फ चार भारतीय खिलाड़ी ही इस टीम में ऐसे हैं जो यहां पहले भी खेल चुके हैं। इनमें स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत शामिल हैं। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही टेस्ट में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा के पास लीड्स में इतिहास रचने का मौका है। संयोग से ये तीनों ही यहां एक-एक मैच खेले हैं और तीनों ने ही दो-दो विकेट अपने नाम किए हैं। अगर इन तीनों में से जो भी 20 जून से खेले जाने वाले टेस्ट में 6 विकेट लेने में सफल हो जाते हैं तो वह भारत के लिए लीड्स में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन जाएगा।

लीड्स में 73 साल पहले भारतीय गेंदबाज गुलाम अहमद ने बनाया था। उन्होंने 1952 में खेले गए एक ही मैच में सात विकेट चटकाए थे। इसके बाद रोजर बिन्नी ने 1996 में सात विकेट अपने नाम कर गुलाम अहमद के रिकॉर्ड की बराबरी की।

अनुराग कश्यप की अपराध शैली में वापसी

(एजेन्सी)। अनुराग कश्यप के प्रशंसक जो एक और गंभीर और रॉ क्राइम ड्रामा देखने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन मौका हो सकता है क्योंकि अपनी गहन और गहरी कहानियों के लिए मशहूर फिल्म निमार्ता निशानची के साथ वापस आ गए हैं, जिसे अमेजन एमजीएम स्टूडियो द्वारा समर्थित किया गया है। इससे भी ज्यादा रोमांचक यह घोषणा है कि यह फि ल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जिसकी थिएट्रिकल रिलीज 19 सितंबर, 2025 को होगी। अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने सोमवार को घोषणा की कि निर्देशक अनुराग कश्यप की आगामी क्राइम ड्रामा फिल्म निशांची 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अजय राय और रंजन सिंह द्वारा जार पिक्चर्स के बैनर तले और फ्लिप फिल्म्स के सहयोग से निर्मित इस फिल्म से ऐश्वर्य ठाकरे अभिनय की दुनिया में कदम रख रहे हैं। उनके साथ वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। निशांची दो भाइयों की उलझी हुई जिंदगियों को दशार्ती है, जो बिल्कुल अलग राहों पर चलते हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे उनके फैसले उनकी किस्मत को गढ़ते हैं। कश्यप ने बताया, यह कहानी वर्ष 2016 में लिखी गई थी और तब से हम एक ऐसे स्टूडियो की तलाश में थे जो हम पर पूरा भरोसा करे। अमेजन एमजीएम ने इसे पसंद किया, यकीन किया और हमारे लिए मजबूत सहारा बना।

पी.डब्ल्यू.डी. यूनियन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मांग पत्र सौंपा: राणा

संजना भारती संवाददाता

पंचकुला। फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों पर कोई सुनवाई न करने पर हरियाणा गवर्नमेन्ट पी.डब्ल्यू.डी. मैकेनिकल वर्कर्ज यूनियन मुख्यालया चरखी दादरी सम्बंधित हरियाणा सयुंक्त कर्मचारी संघ राज्य प्रधान ईश्वर सिंह शर्मा के अध्यक्षता में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ निवास स्थान पर मिला जिसमें 24 सुत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को सोपा मुख्यमंत्री ने यूनियन पदाधिकारी को आश्वासन दिलाया कि सभी मांगों की जांच करवाई जाएगी संगठन चाहता है कि मुख्यमंत्री से जायज कर्मचारियों की मांग है उन पर बातचीत हो जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई विभाग, भवन तथा मार्ग विभाग में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभागों में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी 30 जून 2025 तक स्वीकृति दी गई है 1 जुलाई से कर्मचारियों को कोई स्वीकृति नहीं दी जा रही जिससे पूरे हरियाणा प्रदेश में कार्यरत हजारों हजारों कर्मचारियों को भ्रम है कि विभाग द्वारा नौकरी से न निकाल दिए जाएं जिसके लिए संगठन द्वारा अधिकारियों से बातचीत की तो पता लगा कि पद स्वीकृत नहीं है सन 1987 के पश्चात विभाग द्वारा जल घर तो लगाये है उन पर कर्मचारियों की भरती नहीं हुई ऐसे ही मल्टिपर्प्स वर्कर टर्म अप्वाईंट वेतन की फाईल पास नहीं की गयी सरकार की हिदायतों के अनुसार कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं दी गई है। जबकि ये कर्मचारी पिछले जून 2022 से लगातार अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं।

सरकार द्वारा इन कर्मचारियों का तीन महिने का कार्यकाल तो बढ़ाया गया लेकिन इन कर्मचारियों की पद स्वीकृति नही दी जूलाई 2025 के पश्चात कर्मचारियों को भय है कि कहीं नौकरियां समाप्त न कर दी जांए जन स्वास्थ्य विभाग में चौदह हजार के लगभग कर्मचारी कार्यरत है जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है कुछ कर्मचारियों का ब्लाक 2020-23 का बकाया एल. टी. सी.का भुगतान नहीं किया गया जिसके लिए संगठन ने बार बार लिख कर दिया कई महीने बीत जाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई अगर भुगतान नहीं किया तो दस जून से संगठन हरियाणा प्रदेश में सभी सांसदों व विधायकों सता पक्ष व विपक्ष को मांगों का ज्ञापन सौफना जारी है। अगर कर्मचारियों की मुख्य मांगों के बारे में कोई सुनवाई न हुई तो आपात्त कालीन जून महीने में ही राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुला कर आन्दोलन की घोषणा की जाएगी जिसकी जानकारी आज युनियन के राज्य प्रधान ईश्वर सिहं शर्मा व राज्य महा सचिव सन्दल सिहं राणा ने प्रैस विज्ञप्ति में दी।

उन्होनें बताया कि कर्मचारियों के इ.एस.आई. कार्ड जारी नहीं किये गये हैं जिससे ये कर्मचारी अपना ईलाज करवाने में असमर्थ हैं। कुछ ट्रम अम्पाईंटी व मस्ट्रोल पर लगे कर्मचारियों का पिछले 5 माह से वेतन नहीं दिया ट्रम अम्पाईंटी कर्मचारियों के पी.एफ. व इ.एस.आई. की राशि इनके वेतन से तो काट ली गई है परन्तु इनके पी.एफ व इ.एस. आई. के खाते में राशि नहीं डाली गई है। कर्मचारियों को केन्द्र के समान सभी भत्ता दिया जाए, आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए, फिल्ड मे कार्यरत कुछ कर्मचारियों को मिलने वाली ब्लाक 2020-23 का एल.टी.सी. का आज तक भुगतान नहीं किया गया ब बहाना बनाया जाता है कि एच.आर.डी. विभाग से sop जारी करेगी इसमें कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है 2024-27 ब्लाक के बिल पास करने शुरू कर दिए है जबकि जन स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग में पिछले 2020-23 ब्लाक का भुगतान नही हुआ और 2018 से हरियाणा स्टाफ सलैक्शन ने भर्ती किया और विभागों में भेज दिया है कोमन कैडर हरियाणा स्तर पर बनाया है उसे विभागिय स्तर पर बनाया जाए जिससे उनकी पदोन्नतिहो सके जिसका पत्र मुख्य मंत्री नायब सिहं सैनी को लिखित में युनियन ने दिया परंतु कोई भी सुनवाई आज तक नहीं हुई सरकार ने अगर समय रहते उपरोक्त मांगों का समाधान बातचीत से नहीं किया गया तो मजबूरन संगठन को संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित, 1205 प्रतिभागियों ने लिया भाग: डॉ. सतपाल

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. सतपाल ने बताया कि आयुष विभाग के महानिदेशक संजीव वर्मा के निदेर्शानुसार तथा उपायुक्त उत्तम सिंह के मार्गदर्शन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की जिला स्तर पर बनाई गई नोडल अधिकारी मोनिका के दिशा निर्देशन में जिला करनाल में 11 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफलतापूर्वक मनाने व हरित योग अभियान तथा योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा के तहत विभागीय निदेर्शानुसार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

आयुष विभाग के योग विशेषज्ञ डॉ अमित पुंज ने बताया कि आयुष विभाग करनाल द्वारा चलाए जा रहे हैं विभिन्न योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में करीब 1205 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि आयुष विभाग करनाल द्वारा कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में योग कॉन्फ्रेंस व वर्कशॉप एवं जिला कारागार करनाल में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का कार्यक्रम डायरेक्टर डॉक्टर महेंद्र कुमार गर्ग की देखरेख में आज योग सम्मेलन एवं वर्कशॉप का आयोजन ऑडिटोरियम हॉल में किया गया। योग कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डायरेक्टर डॉ महेंद्र गर्ग ने योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि की फोटो के समक्ष दीप प्रज्वल प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित करके किया। इस दौरान जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर सतपाल, प्रोफेसर डॉ शरत गुप्ता, डिप्टी डीन डॉ गौरव कंबोज, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ अर्चना भारती, हेल्थ इंस्पेक्टर श्री मनोज, डॉ मनोज मित्तल, अतुल जैन डॉ नितिन रोहिल्ला ने भी पुष्पांजलि अर्पित की।

इस दौरान डॉ अमित ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताया एवं हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है हमारा मस्तिष्क चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन मन के तल पर कार्य करता है और ध्यान के माध्यम से हम किस प्रकार अपने मस्तिष्क में नकारात्मक विचार व तनाव को दूर कर-के शांति और आनंद पा सकते हैं अंत में डॉ अमित ने बताया कि जिन खोजा तिन पाइया के माध्यम से बताया कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलता परमात्मा आपके भीतर निवास करता है और हमें ध्यान द्वारा उसको प्राप्त करना है यही योग का उद्देश्य है और मानव जीवन का लक्ष्य है।

इसी प्रकार द्वितीय कार्यक्रम जिला कारागार करनाल में जेल अधीक्षक जिला कारागार करनाल लखबीर सिंह बराड़ की अध्यक्षता में तथा डीएसपी चरण सिंह, डीएसपी शैलाक्षी भारद्वाज व डीएसपी विवेक सांगवान की देखरेख में जिला कारागार करनाल में 31 मई से 21 जून तक आयुष विभाग करनाल द्वारा विशेष योग शिविर लगाया जा रहा है। जिसके तहत सोमवार को 805 कैदियों ने भाग लिया जिसमें योग सहायक गीता दहिया द्वारा महिला कैदियों को तथा मुकेश कुमार द्वारा पुरुष कैदियों को अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल का नियमित अभ्यास करवाया जा रहा है।

बारा न्यायालय में हेड पेशकार दिनेश कुमार का हुआ प्रमोशन

संजना भारती संवाददाता
मनोज कुमार बिन्द

प्रयागराज। प्रयागराज के यमुनापार के अंतर्गत उपस्थित बारा न्यायालय के हेड पेशकार दिनेश कुमार की कार्य कुशलता व उनके लगन को देखते हुए उनका प्रमोशन गत 05 जून को हुआ था। जिसमें उनके द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य को भी सराहा गया। दिनेश कुमार का प्रमोशन 10 दिन पूर्व हुआ था किंतु 16 जून को सहायक पुलिस आयुक्त कौंधियारा विवेक यादव द्वारा उनके कंधे पर दो सितारा लगा कर उनको दरोगा बनने की बधाई दी गई तथा सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा सभी

को दिनेश कुमार के जैसे बनने के लिए प्रेरित किया गया। सितारा लगने के दौरान दरोगा दिनेश कुमार भावुक हो गए। दिनेश कुमार से बात करने पर उनके बताया गया कि एक पुलिस विभाग के लिए उन्होंने सदैव कर्मठता की भावना रखते थे तथा विभाग को अपना परिवार मानते थे जो उनके छोटे थे उनसे छोटे भाई की तरह व्यवहार करते थे तथा जो बड़े थे उनसे आदर व सम्मान के साथ पेश आते थे। न्यायालय में उनके साथ कार्यरत का0 आशीष प्रजापति का कहना था कि दीवान जी सिर्फ उनके हेड नहीं थे बल्कि उनके बड़े भाई थे। उनके प्रमोशन के बाद सबसे ज्यादा खुशी हमें मिली है कि हमारे बड़े भाई अब अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और उनकी जहां आवश्यकता होगी पुलिस विभाग में वह सदैव तत्पर रहेंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महापौरों को बताया शहरों के विकास का सारथी

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महापौर अपने-अपने शहरों के प्रथम नागरिक होने के साथ-साथ वहां के विकास और प्रगति के प्रत्यक्ष सारथी भी हैं। उन्होंने कहा कि महापौर सरकार की नीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, नागरिकों की आकांक्षाओं को समझते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना में महापौर रीढ़ के समान हैं। मुख्यमंत्री श्री सैनी आज पंचकूला में आयोजित अखिल भारतीय महापौर कार्यकारी परिषद की 115वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में महापौर जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और उनके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। यह व्यवस्था नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के बीच मजबूत सेतु बनाती है और निर्णय प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह तथा प्रभावी बनाती है। उन्होंने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तब शहरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। शहर केवल निवास

स्थान नहीं हैं, बल्कि आर्थिक विकास के इंजन, नवाचार के केंद्र और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के संगम हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अर्बनाइजेशन को चुनौती नहीं, अवसर मानते हैं। हमारा विजन है कि शहर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का संगम बनें। हमें शहरों को केवल इमारतों और सड़कों का ढांचा नहीं बनाना, बल्कि उन्हें जीवंत, संवेदनशील और आत्मनिर्भर भी बनाना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत की लगभग 900 मिलियन आबादी शहरों में निवास करेगी। यह सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि एक बड़ी संभावना है। नए अवसरों, नए इन्फ्रास्ट्रक्चर और नई जीवनशैली की। हमें इस परिवर्तन को सुनियोजित शहरीकरण, डिजिटल एकीकरण और पर्यावरण संरक्षण के साथ अपनाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए 2014-15 में 1,693 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी, जिसे 2025-26 में बढ़ाकर 5,666 करोड़ रुपये कर दिया गया है। चार मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं और फरीदाबाद व करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत फरीदाबाद में 930 करोड़ रुपये की लागत से 45 परियोजनाएं तथा करनाल में 927 करोड़ रुपये की लागत से 122 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 2,147 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया है और नई अधिकृत कॉलोनियों में एक हजार करोड़ रुपये से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत मिशन के तहत अब तक 2,930 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 375 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लक्ष्य में से 9 शहरों में 50 बसें चलाई जा चुकी हैं और प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 2026 तक 450 बसें खरीदी जाएंगी।

पंजाब कैबिनेट सब-कमेटी ने की 12 कर्मचारी यूनियनों से बैठकें, जायज माँगों पर शीघ्र कार्रवाई का दिया भरोसा

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब-कमेटी ने यहाँ लगभग एक दर्जन कर्मचारी यूनियनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करते हुए उनकी माँगों व मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर कमेटी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जायज मुद्दों के समाधान हेतु समयबद्ध ढंग से आवश्यक कार्रवाइयाँ तेज की जाएँ।

पंजाब सिविल सचिवालय स्थित वित्त मंत्री के कार्यालय में लगभग चार घंटे तक चली बैठकों में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कुलदीप सिंह धालीवाल और डॉ. रवजोत सिंह द्वारा विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों से सार्थक संवाद किया गया।

बैठकों में भाग लेने वाली यूनियनों में कंप्यूटर अध्यापक संघर्ष कमेटी, सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन, सर्व शिक्षा अभियान/मिड-डे मील दफ्तरी कर्मचारी यूनियन, पीएस टैट पास डीपीई यूनियन, बेरोजगार पीएस टैट आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, आदर्श स्कूल टीचिंग व नॉन-टीचिंग कर्मचारी यूनियन, पावरकॉम ट्रांसको

आउटसोर्स वर्कर यूनियन, मानभत्ता वर्कर साझा मोर्चा, पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन, जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ वेट्स फॉर पे पैरिटी तथा पंजाब रोडवेज स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन शामिल थीं।

बैठकों के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने यूनियन नेताओं द्वारा सौंपे गए माँग पत्रों में उठाए गए बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संबंधित विभागों को कर्मचारियों की जायज माँगों के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भंडारी, व्यय सचिव वी.एन. जादे, परिवहन सचिव वरुण रूजम, कार्मिक सचिव गुरप्रीत कौर सपरा और शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा को उनके विभागों से संबंधित माँगों पर समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए।

वित्त मंत्री ने कर्मचारी यूनियनों को आश्वासन दिया कि उनकी माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और निष्पक्ष ढंग से समय पर समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों की समस्याओं को रचनात्मक संवाद के माध्यम से सुलझाने और समय पर कार्रवाई कर उनके हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठकों में भाग लेने वाले यूनियन प्रतिनिधियों में कंप्यूटर अध्यापक संघर्ष कमेटी से जोली सिंगला, कुलदीप सिंह, कुलविंदर सिंह; सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियंस से देव राज वर्मा, मख्खन सिंह, जसमेर कौर; सर्व शिक्षा अभियान/मिड-डे मील दफ्तर कर्मचारी यूनियन से रजिंदर सिंह, परवीन शर्मा, जगमोहन सिंह; पीएस टैट पास डीपीई यूनियन से रमनप्रीत सिंह, मलकीअत सिंह, हरदीप सिंह; बेरोजगार पीएस टैट आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन से राकेश कुमार, हरबंस सिंह, किरणदीप कौर; डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट से विक्रम देव सिंह, महिंदर कुमार, डॉ. टीना; आदर्श स्कूल टीचिंग व नॉन-टीचिंग यूनियन से जसबीर सिंह, अमरजोत जोशी, सुखदीप कौर; पावरकॉम ट्रांसको आउटसोर्स वर्कर यूनियन से हरविंदर शर्मा, मनदीप सिंह, मनदीप कौर; मानभत्ता वर्कर साझा मोर्चा से ममता शर्मा, मनदीप कौर, शकुंतला शर्मा; पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन से गुरनाम सिंह विरक, तरसेम सिंह, अनुज कुमार; जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ वेट्स फॉर पे पैरिटी से डॉ. जतिंदर सिंह, डॉ. पुनीत, डॉ. जसलीन कौर तथा पंजाब रोडवेज स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन से हरमिंदर सिंह व उनके साथी शामिल थे।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और उनके स्टाफ ने बनवाए आभा कार्ड

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने आज अपना और अपने स्टाफ का आभा कार्ड बनवाया। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य एक सहज और अंतर संचालन (इंटरऑपरेबल) योग्य डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को डिजिटल बनाना है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और अंतर-संचालनीय डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों का उपयोग करके विभिन्न हितधारकों के बीच निर्बाध डेटा साझाकरण को सक्षम बनाना है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ उठाना है। यह योजना कड़े डेटा सुरक्षा उपायों के साथ बनाई गई है। रोगी का डेटा केवल स्पष्ट सहमति से साझा किया जाता है। स्वास्थ्य डेटा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के पास रहता है; एबीडीएम संवेदनशील स्वास्थ्य डेटा को केंद्रीकृत रूप में संग्रहीत करने के बजाय सुरक्षित आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। कुछ डेटा (आभा, एचपीआर, एचएफआर) को अंतर संचालनीयता और विश्वास के लिए केंद्रीय रूप से संग्रहीत किया जाता है।

मरीज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को अपनी आभा (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) आईडी से लिंक कर सकता है। वह अपनी सहमति से डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से संग्रहीत, एक्सेस और साझा कर सकता है। हरियाणा में संचालन के लिए एबीडीएम टीम जागरूकता पैदा करने और आभा आईडी बनाने की सुविधा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन राज्य मिशन निदेशक श्रीमती संगीता तेतरवाल के नेतृत्व में चलाया जा रहा है।

इस अवसर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) श्री कैलाश सोनी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आभा कार्ड बनाने के लाभ बताए और इस मिशन के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भिन्न होने के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में अब तक 1.63 करोड़ से अधिक आभा कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीएचसी मुलाना को आभा कार्ड धारकों के लिए प्रदेश का पहला आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बनाया गया है, जो पूरी तरह कार्यात्मक है। यहां मरीज ऑनलाइन पंजीकरण कराकर इलाज करा सकते हैं। सीएचसी मुलाना में मरीजों को पंजीकरण के लिए लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही यह योजना राज्य के सभी 22 जिलों में प्रति स्वास्थ्य संस्थान 2 स्वास्थ्य केंद्रों यानि कुल 44 स्वास्थ्य संस्थानों में लागू की जाएगी। स्वास्थ्य संस्थानों के डिजिटलीकरण के क्षेत्र में यह एक नई और परिवर्तनकारी पहल साबित होगी।

बैठक में तकनीकी टीम के सदस्य - आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के परियोजना प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) श्री डार्विन अरोड़ा और एचएमआईएस प्रबंधक श्री उमेश सैनी भी मौजूद रहे।

पंजाब सरकार ने आरसी और डीएल के बैकलॉग संबंधी लिया बड़ा फैसला; क्षेत्रीय अधिकारियों को दिए गए पंजीकरण अधिकार

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पंजीकरण प्रमाणपत्रों (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंसों (डीएल) के पंजीकरण और नवीनीकरण के अधिकार क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंप दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य आरसी और डीएल पंजीकरण तथा नवीनीकरण के वर्षों से लंबित बैकलॉग कार्य को पूरा करना है और आम जनता को बड़ी राहत प्रदान करना है।

पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के नागरिक एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर इस राहत का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब आवेदक अपने पुराने वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन करवा सकते हैं और संबंधित दस्तावेजों का नवीनीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुराने आरसी और डीएल के नवीनीकरण से संबंधित दस्तावेजों की स्वीकृति और उनका ऑनलाइन न होना एक बड़ी बाधा बना हुआ था।

मंत्री ने बताया कि पंजाब के सभी पंजीकरण अधिकारियों और लाइसेंसिंग अधिकारियों को एक लिखित पत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और बैकलॉग को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय द्वारा 24 मई, 2024 को जारी पत्र की शर्तों के अनुसार निपटाने के लिए कहा गया है। स. भुल्लर ने बताया कि आरसी और डीएल के बैकलॉग के संबंध में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सत्यापित हलफनामा लिया जाएगा। इस हलफनामे में बैकलॉग के माध्यम से ऑनलाइन कराने, अवधि, श्रेणी, मैनुअल जारी करने वाले प्राधिकरण, कर भुगतान और कोई बकाया न होने तथा सभी जानकारी के सही होने संबंधी प्रविष्टि करनी होगी।

परिवहन मंत्री ने बताया कि आरसी के बैकलॉग को ऑनलाइन करते समय, जिस वाहन पर पंजीकरण नंबर लगा है, उसका मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा चेसिस और इंजन नंबर के पूरे विवरण के साथ भौतिक जांच रिपोर्ट भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आरसी बैकलॉग करते समय विभिन्न व्यक्तियों के वाहन हस्तांतरण रिकॉर्ड भी अपलोड किए जाएं, ताकि पिछले मालिकों का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जा सके। स. भुल्लर ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के बैकलॉग के संबंध में, आवेदन मूल प्राधिकरण के माध्यम से किया जा सकेगा। डीलिंग स्टाफ कार्यालय रिकॉर्ड से पहले और बाद में जारी किए गए लाइसेंस की प्रमाणित/सत्यापित प्रति को सारथी सॉफ्टवेयर में अपलोड करेगा, जिसके बाद लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा उसे अनुमोदित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान लाइसेंस की मूल प्रति और जन्म/पते के प्रमाण भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

मंत्री ने बताया कि बैकलॉग के कार्य को पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए विभाग का एक स्थायी कर्मचारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस/आरसी से संबंधित बैकलॉग की प्रविष्टि कार्यालय में दर्ज करेगा, उसे परिवहन पोर्टल पर सत्यापित करेगा, और इसके बाद संबंधित प्राधिकरण द्वारा उसे अनुमोदित किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी गलत प्रविष्टि की पूरी जिम्मेदारी संबंधित पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण की होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आरसी और डीएल बैकलॉग अनुमोदन की दैनिक रिपोर्ट मुख्यालय को निर्धारित प्रोफार्मा में भेजी जाए।

ज्ञान, न्याय, सेवा, व्यापार और उद्योग एक साथ मिलकर राष्ट्र की नींव को कर रहे और अधिक मजबूत: कृष्ण लाल पंवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले 11 साल में देश ने विकास में लगाई लंबी छलांग

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। हरियाणा के विकास एवं पंचायत, खनन एवं भूविज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, व्यापारी और उद्योगपति भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम योगदान दे सकते हैं। ये वर्ग ज्ञान, न्याय, सेवा, व्यापार और उद्योग के माध्यम से राष्ट्र की नींव को मजबूत बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले 11 साल में देश ने विकास में लंबी छलांग लगाई है। इसी का नतीजा है कि देश आज दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विकास की इसी गति से देश तय अवधि तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने अनुसार विकसित राष्ट्र होगा।

मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार सोमवार को कमेटी चौक स्थित सनातन धर्म मंदिर में आयोजित प्रोफेशन मीट में बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा वरिष्ठ नेता बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के सह-संयोजक रविभूषण गर्ग ने की। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रही। अपने संबोधन में मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत-विकसित हरियाणा की और तेजी से अग्रसर है। यह सम्मेलन, केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि विकसित भारत-विकसित हरियाणा के निर्माण की एक झलक है। ये सभी वर्ग ज्ञान, न्याय, सेवा, व्यापार और उद्योग एक साथ मिलकर राष्ट्र की नींव को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र को मजबूत बना रहे हैं। प्रोफेसर्स से अपील है कि वे स्किल और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाएं। इसी प्रकार से डॉक्टर जन स्वास्थ्य के मिशन में भागीदारी निभा रहे हैं। वकील समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने में योगदान देते हैं। व्यापारी स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों से जोड़ें और उद्योगपति नवाचार, स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करें।

हरियाणा के विकास एवं पंचायत, खनन एवं भूविज्ञान मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने समावेशी विकास की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमने ज्ञान को रोजगार से जोड़ा है, शिक्षा को समावेशी बनाया है और शोध को प्रोत्साहन दिया है। वर्तमान सरकार ने हर 20 किलोमीटर में एक कॉलेज खोलने का काम किया है। आज प्रदेश में कुल 185 कॉलेज है। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 80 कॉलेज खोले है। इनमें से 30 कॉलेज केवल लड़कियों के हैं। जबकि, कांग्रेस के राज में केवल 44 खोले गए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ई-कोर्ट्स और न्याय प्रणाली के डिजिटलीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से 1500 से अधिक निरर्थक व पुराने केंद्रीय कानूनों को निरस्त किया है। सरकार ने देश की प्रगति, समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनेक ऐतिहासिक कानून लागू किए हैं। आज देश सुरक्षित हाथों में है और दुश्मन को करारा जवाब दिया जाता है।

मंत्री कृष्ण पंवार ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूलमंत्र को साकार करने वाले सशक्त उपकरण हैं। भारत अब न्याय और विकास की दिशा में नई गति से आगे बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से वर्तमान सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को हर गरीब के घर तक पहुंचाया है। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जबकि वर्ष 2014 से पहले केवल छह मेडिकल कॉलेज थे।

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने व्यापार के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को सुधारने का कार्य किया, कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया। जहां व्यापारी वर्ग लोगों को रोजगार देने के साथ साथ समाज को आगे भी बढ़ाते हैं। जीएसटी को व्यापारी वर्ग की मदद से ही सफल बनाया जा सका है। आज भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में उद्योगपतियों का बड़ा योगदान है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाएं आपके आत्मविश्वास पर ही आधारित हैं। हमारा लक्ष्य हरियाणा को 2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलना और 50 लाख नए रोजगार सृजित करना है। हरियाणा सरकार ने भविष्य की प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाया है। प्रदेश के हर जिले को एक एक्सपोर्ट हब बनाना हमारा सपना है। आप सब वोकल फॉर लोकल से आगे बढ़कर लोकल टू ग्लोबल की यात्रा तय करें। सरकार और आपके संयुक्त प्रयास से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। आढ़तियों का कमीशन 46 से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति ट्रिल किया गया है। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 11 साल में संकल्प से सिद्धि तक को सार्थक किया है। देश विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में जनकल्याण की दिशा में काम कर रही है।

असंध विधायक योगेंद्र राणा का विभिन्न कार्यक्रमों में जोरदार स्वागत करते हुए। (छाया: एसबी)

असंध नगर पालिका चेयरपर्सन सुनीता रानी ने सफाई कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असंध। स्वछता पखवाड़े अंतर्गत व शहरी स्थानीय निकाय विभाग पंचकूला के आदेश अनुसार नगरपालिका सचिव प्रदीप कुमार जैन व नपा चेयरपर्सन सुनीता अरडाना के नेत्तृत्व में स्वच्छता अभियान में पूरी तरह से अपनी भागीदारी देने वाले सभी सफाई कर्मचारियों को नपा चेयरपर्सन सुनीता अरडाना द्वारा प्रसंशा पत्र दे कर सम्मानित कर हौसला बढ़ाया। इस अवसर चेयरपर्सन सुनीता अरडाना ने बताया की स्वच्छ अभियान के तहत स्वच्छता के सिपाहियों को प्रसंशा पत्र देकर सम्मानित किया गया है, सम्मान पाकर सफाई कर्मचारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे, चैयरपर्सन ने आमजन से अपील की की अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने आसपास कूड़ा इक्कठा न होने दे और कूड़ा नगरपालिका की गाड़ी डालें। स्वच्छ भारत प्रेरक जसमेर ने आमजन से आग्रह किया की हर नागरिक स्वच्छ अभियान जुड़े और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करें इसकी जगह कपडे जुट आदि का बैग प्रयोग करें और अपने नगर को स्वच्छ बनाये।

इस मौके पर राजपाल भट्ट, सोनू गावस्कर, जसमेर प्रेरक, विक्रम सफाई दरोगा, जसवंत मनोज, सुशिल अनिल, वीरभान, सोनू बोहत व अन्य सफाई कर्मचारी मौजूद रहे।

नपा राजौद में प्रशासनिक निर्देश अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा जोर-शोर से मनाया जा रहा है

नपा सचिव नरेंद्र शर्मा ने सफाई कर्मचारियों को 'सफाई कर्मचारी कल्याण किट' व प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। नगर पालिका राजौद में प्रशासनिक निर्देश अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा जोर-शोर से मनाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत नपा सचिव नरेंद्र शर्मा द्वारा सफाई कर्मचारियों को 'सफाई कर्मचारी कल्याण किट' व प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

नपा सचिव नरेंद्र शर्मा ने बताया कि सफाई कर्मचारी सुबह से शाम तक सफाई कार्य करते हुए नागरिकों की सेवा में तत्पर रहते हैं। यदि एक दिन भी सफाई कर्मचारी किसी वार्ड में ड्यूटी पर न पहुंचे तो उस वार्ड के नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। घरों व गलियों में कूड़े-कचरे के ढेर लग जाते हैं। सफाई कर्मचारी उस कचरे को साफ करता है जिससे आम नागरिक अपने घर से बाहर फेंक देता है। वह गलियों, नालियों की सफाई करता है ताकि हमारा नगर, हमारी गलियां व सड़के साफ सुथरी रहे और नागरिक बीमारियों से बचे रहे। बरसात होने पर हमारे नाले अवर फ्लो ना हो।

सफाई कर्मचारी गर्मी, सर्दी, बारिश, आंधी, तूफान की परवाह किए बगैर, अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर हमेशा ड्यूटी पर मुस्तैद रहता है। हम सबको इनका सम्मान करना चाहिए। सचिव ने कहा कि समय-समय पर सरकार व जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार नगर में सफाई व्यवस्था कायम रखने व पॉलीथिन का प्रयोग न करने बारे जागरूकता अभियान चलाए जाते रहे हैं। उन्होंने मंच से सभी नागरिकों को प्रेस के माध्यम से आह्वान किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। दुकानदार जूट या कपड़े के थैले का प्रयोग करें। सफाई व्यवस्था बनाए रखने में नगर पालिका का सहयोग करें।

सफाई कोर्डिनेटर प्रदीप कुमार धाँदी ने नपा राजौंद क्षेत्र के नागरिकों से अनुरोध किया कि नपा सफाई कर्मचारियों का सहयोग करें। आपके सहयोग के बिना सफाई व्यवस्था कायम रखना संभव नहीं है। घर का कूड़ा कचरा गली में न डालें, बल्कि डोर टू डोर वाले वाहन में डालें। फल व सब्जियों के छिलके लिफाफे में डालकर नाले में या गलियों में न डालें। सभी नागरिक बाजार से सम्मान खरीदने जाते समय जूट या कपड़े का थैला लेकर जाएं। किसी भी दुकानदार से प्लास्टिक के थैले में कोई भी वस्तु ना ले। उन्होंने दुकानदारों से भी अनुरोध किया की सिंगल यूज प्लास्टिक के थैले में सामान देना बंद करें व जूट या कपड़े के थैले का प्रयोग करें।

इस अवसर पर नपा सचिव नरेंद्र शर्मा, कोर्डिनेटर प्रदीप कुमार धाँदी, जेई अश्वनी कुमार, लेखाकार कर्म सिहं, सभी सफाई कर्मचारी व कार्यालय स्टाफ मौजूद रहा।

जींद-कैथल की सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने ओवरलोड डम्फरो पर की रेड

2 लाख 3 हजार रुपए का किया गया चालान

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल/राजौंद। गुप्तचर विभाग कैथल की सूचना पर सीएम फ्लाइंग जींद-कैथल की संयुक्त टीम ने राजौंद क्षेत्र में चल रहे ओवरलोड वाहनों पर रेड की। रेड के दौरान गांव सेरधा में राजौंद-पुंडरी मार्ग पर नजदीक बस स्टैंड गांव सेरधा से 4 मिट्टी से भरे हुए ओवरलोड डम्फरो को काबू किया गया। जिसके बाद सभी डम्फरो को बस स्टैंड पूंडरी में बंद करते हुए नियमों का उल्लंघन करके चल रहे डम्फरो का कुल 2 लाख 3 हजार रुपए का चालान करके इंपाउंड किया गया। रेड के दौरान मुख्य रूप से शीशपाल-क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कैथल, पवन कुमार व बिजेंद्र सिंह सीएम फ्लाइंग अधिकारी मौजूद रहे। सीएम फ्लाइंग की रेड से क्षेत्र के वाहन चालकों में हड़कंप मच गया।

अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने पर आवर लोडेड वाहनों पर आगे भी सीएम फ्लाइंग की पैनी नजर रहेगी।

पूर्वजों ने मेहनत मजदूरी के बलबूते समाज में सम्मान पूर्वक अपनी पहचान बनाई: शेरू विंग

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असन्ध। अखिल भारतीय पंजाबी खत्री स्वयंसेवक संघ की करनाल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में बैठक का आयोजन समाजसेवी पुरुषोत्तम ठुकराल की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरु विंग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्य अतिथि का नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेश ठुकराल भाजपा मंडल अध्यक्ष हिमांशु छाबड़ा, नितिन जुनेजा, सनातन धर्म मंदिर कमेटी के प्रधान विक्की जुनेजा व विशु चोपडा उनको पटका पहना व अरुट जी महाराज का स्वरूप भेंट कर स्वागत किया। बैठक में संघ की स्थानीय इकाई का गठन किया गया। जिसमें योगेश ठुकराल को सर्वसम्मति से असन्ध इकाई का प्रधान चुना गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल शेरू विंग ने सामाजिक एकता एवं पंजाबी समाज के उत्थान पर जोर देते हुए कहा कि 1947 के देश विभाजन विभाजन में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा पंजाबी खत्री समाज के लोगों का नरसंहार हुआ। उनके पूर्वज धर्म के खातिर अपना सब कुछ छोड़कर पलायन करके शरणार्थी कैंपों में शरण ली। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने मेहनत मजदूरी के बलबूते समाज में सम्मान पूर्वक अपनी पहचान बनाई और बच्चों का पालन पोषण किया। उन्होंने कहा कि आज पंजाबी खत्री समाज हर क्षेत्र में पूरा योगदान कर रहा है। परंतु उनके हितों के अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति को अब जागरुक का करने का समय आ गया है।

इस अवसर पर युवा नेता डॉ हिमांशु छाबड़ा, विक्की जुनेजा बादल छाबड़ा व पारुल गांधी ने कहा कि युवा समाज को अपने हितों और अधिकारों के लिए मजबूती के साथ आगे आना होगा। इसलिए संघ की मजबूती के लिए एक जुट होकर काम करें। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरू विंग व कार्यकारिणी कमेटी व सदस्यों ने नव निर्वाचित प्रधान योगेश ठुकराल को पटका पहना व अरुट जी महाराज का स्वरूप भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर नव नियुक्त प्रधान ठुकराल ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह उसे सच्ची निष्ठा व लगन से निर्वहन करेंगे। इस अवसर पर नितिन जुनेजा यश लूम्बा, शाम चुघ, ट्विंकल ठुकराल, चेतन चानना सहित अन्य उपस्थित रहे।

संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरु विंग को अरुट जी महाराज स्वरूप भेंट करते आयोजक। (छाया: एसबी)

पंचों के गुप्त फैसले के आधार पर सहमत हुए आंदोलित किसान

मुस्तफाबाद गांव में 13 दिन से चल रहे धरने को किया समाप्त

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। मुस्तफाबाद गांव के रकबे में गत 13 दिनों से लगातार चल रहा धरना पंचों द्वारा किए गए गुप्त फैसले के आधार 4 गांव के आंदोलित किसानों ने सहमति से धरने को उठा लिया गया है। इस मसले को हल करने के लिए किसानों व ठेकेदार की ओर से 2-2 पंच नियुक्त करके एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी में ठेकेदार की ओर से फूंसगढ गांव धर्मबीर लाठर व मंगलोरा गांव के सतबीर सिंह तथा किसानों की ओर से गांव ढाकवाला गुजरांन के चंद्रभान करनाल से मुकेश कुमार को शामिल किया गया था। भाकियू की ओर से इस कमेटी में कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ था। किसानों व ठेकेदार की सहमति से गठित की गई कमेटी ने मौखिक रूप से किसानों को अपने विश्वास में लेते हुए फैसले को गुप्त रख लिया गया है। जिस पर धरने पर उपस्थित किसानों ने अपनी अपनी सहमति देते हुए अपने धरने को उठा लिया और अपने खेत रेत ड़ालने की कथित सहमति दे दी। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष रतनमान ने बताया कि किसानों की सहमति के चलते धरने को खत्म करने की घोषणा कर दी है।

इस अवसर पर राम सिंह मुस्तफाबाद, पालाराम ढ़ाकवाला गुजरांन, अनिल, सुमित चौधरी, मनोहर लाल, महाबीर सिंह, दिलावर सिंह सहित कई किसान मौजूद थे।